Publication	**Punjab Kesri**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Banwari Kumawat
Date	17/07/2025	**Page no**	8
CCM	28.65		

Amit Shah will give big gifts to the people of Rajasthan

राजस्थान वासियों को बड़ी सौगातें देंगे अमित शाह

- आठ हजार से अधिक युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र
- श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की होगी लॉन्चिंग

जयपुर, (बनवारी कुमावत): केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में गुरूवार (17 जुलाई) को जयपुर जिले के दादिया ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प की सिद्धि की दिशा में प्रदेश को सहकारिता के क्षेत्र में बड़ी सौगातें देंगे। जिससे किसान, गरीब, महिला सहित विभिन्न वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। श्री शाह विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं चैक वितरण तथा सहकारिता की विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। श्री शाह विश्व की वृहत अन्न भण्डारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण करेंगे। साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रूपये का ऋण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2346 माइक्रो एटीएम का वितरण करने के साथ ही श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग भी करेंगे। इस दौरान श्री शाह द्वारा थानों, सशस्त्र बलों, ट्रूप कैरियर तथा प्रशिक्षण के लिए 100 नए पुलिस वाहनों का फ्लैग-ऑफ भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्सवों के माध्यम से निरंतर नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरूवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री रोजगार उत्सव के तहत 8 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में श्री शाह सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Rajasthan Patrika**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	17/07/2025	**Page no**	2
CCM	14.88		

Home Minister Amit Shah on Jaipur tour today

सहकार-रोजगार उत्सव

गृहमंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर

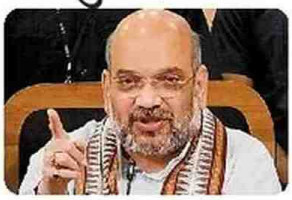

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। वे जयपुर में रिंग रोड स्थित ग्राम दादिया में अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत आयोजित सहकार एवं रोजगार उत्सव को सम्बोधित करेंगे। शाह दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कार्यक्रम स्थल दादिया पहुंचेंगे और करीब ढाई घंटे विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृहमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बुधवार रात तक तैयारियां चलती रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया।

कार्यक्रम में प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के करीब एक लाख सहकार प्रतिनिधियों को बुलाया गया हैं। उसी के अनुरूप तीन डोम में बैठने की व्यवस्था की गई हैं। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री शाह श्वेत क्रांति-2.0 के तहत पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लांचिंग करेंगे।

Downloaded from
SAMVAD

Publication	**Dainik Jagran (Rashtriya)**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Bureau
Date	17/07/2025	**Page no**	9
CCM	92.09		

Self-reliant and prosperous village

मंथन

आत्मनिर्भर एवं खुशहाल गांव

गांवों को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से आरंभ किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभाव महज चार वर्षों में ही दिखने लगा है। वहीं, सहकारिता माडल धरातल पर सफल होता दिख रहा है

नीलू रंजन

nranjan@del.jagran.com

प्रतीकात्मक

महानगरों की चकाचौंध और अर्थव्यवस्था के बड़े-बड़े आंकड़ों के बीच ग्रामीण जीवन में शांत, लेकिन व्यापक परिवर्तन की आहट मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब वर्ष 2021 में देश में पहली बार सहकारिता के लिए अलग से मंत्रालय आरंभ किए जाने की घोषणा की, तो इसकी असली अहमियत के बारे में शायद ही किसी को अंदाजा होगा। लेकिन चार वर्षों में ही अमित शाह के नेतृत्व में यह मंत्रालय एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और डाटा आधारित माडल के साथ ग्रामीण इलाकों में आम आदमी के जीवन में बड़े बदलाव का वाहक बनकर उभरा है।

एक ओर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बिना किसी बिचौलिए और शुल्क के किसानों को ऋण मुहैया कराकर उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्ति दिला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति से जुड़ी स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका जीवन संवारने का काम कर रहा है। एक समय में अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए चिंतित रहने वाली आदिवासी महिलाएं पोल्ट्री और डेयरी व्यवसाय से सालाना लाखों रुपये की कमाई कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाला सस्ता सरकारी ऋण ग्रामीण इलाकों में लखपति दीदियों की नई फौज तैयार कर रहा है। देखा जाए तो असली भारत हमारे गांवों में ही बसता है, जहां पहली बार सहकार से समृद्धि दस्तक दे रही है।

वैसे तो भारत सहकारी क्षेत्र की सफलता से पुराने समय से ही परिचित है। अमूल और इफको जैसी संस्थाएं दशकों से दुनिया में अग्रणी भूमिका में रही हैं। इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस ने 2024 में इन्हें दुनिया भर में टर्नओवर-टू-जीडीपी- प्रति व्यक्ति अनुपात के आधार पर पहले और दूसरे स्थान पर रखा था। ये उपलब्धियां पहले केवल प्रतिष्ठित ब्रांड्स तक सीमित थीं। लेकिन सहकारिता मंत्रालय अब उन्हें अंतिम छोर तक पहुंचा रहा है। दरअसल सहकारिता मंत्रालय ने लंबे समय से चली आ रही बिखरी और अप्रभावी सहकारी नीतियों से एकजुट और समन्वित तरीके से प्रभावी बनाने का प्रयास किया है।

सहकार से समृद्धि : सहकारिता मंत्रालय का सोच ''सहकार से समृद्धि'' पर आधारित है, जिसके माध्यम से एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और डाटा-आधारित माडल के माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव लाना है। आजादी के बाद से उपेक्षित सहकारिता क्षेत्र को पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का काम शुरू किया गया। इसके तहत 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 67 हजार से अधिक पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो रहा है और इन्हें कामन सर्विस सेंटर के रूप में बदला जा रहा है, जिसमें तीन सौ से अधिक सरकारी सेवाएं जैसे आधार का अपडेट करने और रेल टिकट बुकिंग तक की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बड़ी मात्रा में सहकारी समितियों को सस्ता ऋण उपलब्ध करा रहा है। पिछले तीन वर्षों में यह 25 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.28 लाख करोड़ रुपये हो गया है। आज की तिथि में साढ़े आठ लाख से अधिक सहकारी समितियों और लगभग 30 करोड़ सदस्यों का केंद्रीकृत डाटाबेस है, जिनके आधार पर ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी भागीदारी कुल कृषि ऋण में 20 प्रतिशत, उर्वरक वितरण में 35 प्रतिशत और चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत है। केवल डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियों का देश की जीडीपी में 4.5 प्रतिशत का योगदान है।

सहकारी योजनाएं ग्रामीण इलाकों में व्यापक बदलाव की शुरुआत करने के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी इसे आगे बढ़ने की तैयारी है। इसके लिए सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है, जिसमें ड्राइवर ही कंपनी के सह-मालिक होंगे।

आने वाले समय में मंत्रालय की कोशिश हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना करना है। इसके लिए दो लाख नए पैक्स बनाने होंगे। इससे सहकारिता गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। इन्हें पीएम किसान फसल बीमा और ग्रामीण कौशल विकास योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। सहकारी समितियां अब ग्रामीण विकास और उसमें जन भागीदारी का केंद्र बनकर उभरेंगी। इसके लिए सभी पैक्स को डिजिटल गवर्नेंस उपकरणों और स्थानीय संस्थाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके बाद ये समितियां प्रापर्टी का सत्यापन, ई-केवाइसी, विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं सुचारु रूप से कर सकेंगी। जाहिर है, सरकार का उद्देश्य गांव और उसके निवासियों को उद्यमशील, समावेशी एवं आत्मनिर्भर बनाना है। यह भारत के पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

****

****

Downloaded from SAMVAD